

मुख्य समाचार

- पिछले दो दशकों में प्रदेश के वन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज— वन क्षेत्र बढ़कर हुआ 15 हजार 5 सौ 80 वर्ग किलोमीटर से अधिक।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कनाडा के भारतीय प्रवासियों को हिमाचल में निवेश के लिए किया आमंत्रित।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर आपदा प्रभावितों के प्रति अमानवीय व्यवहार अपनाने का लगाया आरोप।
- प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और निचले इलाकों में वर्षा से तापमान में गिरावट— आगामी 24 घंटों में 8 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट।
- मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने सभी विभागों को सर्दियों से पहले आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा।

सुक्खू

हिमाचल प्रदेश में पिछले दो दशकों में वन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय वन सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का कुल वन क्षेत्र बढ़कर वर्ष 2023 में 15 हजार पांच सौ 80 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है। अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी.....

प्रदेश के वन क्षेत्र में हुई ये वृद्धि राज्य सरकार के सतत वनीकरण, पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन और जन सहभागिता आधारित वन प्रबंधन के सफल प्रयासों का परिणाम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ये उपलब्धि व्यापक पौधरोपण अभियानों, विभिन्न योजनाओं और स्थानीय समुदायों, स्वयं सहायता समूहों व वन सहकारी समितियों की सक्रिय भागीदारी से संभव हुई है। उन्होंने कहा कि महिलामंडलों, युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य पंजीकृत संस्थाओं की भागीदारी से वनीकरण अभियानों को नई गति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक संगठन को पांच हैक्टेयर तक के बंजर या क्षतिग्रस्त वन क्षेत्र को विकसित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी और इस पर प्रति हैक्टेयर अधिकतम एक लाख 20 हजार रूपए तक की राशि प्रदान की जाएगी। संयुक्त वन प्रबंधन और नई भागीदारी आधारित वन पुनर्स्थापन योजनाओं के तहत लोगों को वन संसाधनों का स्वामीत्व और आजीविका से जुड़ा लाभ मिला है, जिससे पारिस्थितिकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कनाडा के भारतीय प्रवासियों को हिमाचल प्रदेश का भ्रमण करने और यहां निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कनाडा के ओटावा स्थित ऐतिहासिक संसद हिल पर आयोजित कुल्लू दशहरा के भव्य समारोह के अवसर पर एक विशेष वीडियो संदेश के माध्यम से भारतीय प्रवासियों को शुभकामनाएं दीं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि 'इस अवसर पर

हिमाचल की समृद्ध संस्कृति के जीवंत रंग पूरी भव्यता के साथ प्रदर्शित होंगे, जिससे विदेश में रह रहे लोगों को भी अपने घर जैसा अनुभव मिलेगा। इस उत्सव में हिमाचल प्रदेश की विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया, जिसमें विश्व प्रसिद्ध हिमाचली लोकनृत्य 'नाटी', पारंपरिक रामलीला का मंचन और सभी अतिथियों को परोसी गई हिमाचली धाम मुख्य आकर्षण रहे। इस आयोजन में 35 से अधिक क्षेत्रीय सामुदायिक संगठनों ने भाग लिया, जो हिमाचली प्रवासियों की एकता और सांस्कृतिक गौरव को प्रदर्शित करता है। इस अवसर पर भारत के कनाडा स्थित उप उच्चायुक्त, वरिष्ठ राजनयिक, सामुदायिक नेता व अन्य विशिष्ट अतिथि भी मौजूद रहे।

मांडविया

केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार 150 एकता मार्च का शुभारंभ किया। डॉ. मांडविया ने कहा कि यह एकता मार्च केवल एक स्मरणोत्सव नहीं है, बल्कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण में शामिल करने और विकसित व आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का एक राष्ट्रीय आंदोलन है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभक्ति और नागरिक जिम्मेदारी की भावना को प्रेरित करना है। डॉ. मांडविया ने बताया कि यह एकता मार्च आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का संदेश देगा। अभियान का पहला चरण इस वर्ष 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक जिले में आयोजित किया जाएगा।

जयराम ठाकुर

पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर आपदा प्रभावितों के प्रति संवेदनहीन व अमानवीय व्यवहार अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आज मण्डी जिले में सराज विधानसभा क्षेत्र के धरबार—थाच और बागाचनोगी में आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार क्षेत्र में आपदा प्रभावितों के पुर्नवास और सड़कों की बहाली के लिए ढुलमुल रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि आपदा से पांडव शीला से धार सड़क बंद है जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सड़क बंद होने के कारण वहां तक मशीन नहीं जा पा रही है और मलबे में दबी तीन लाशें अभी तक भी नहीं खोजी जा सकी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार नाकामी के बाद खुद से सड़क बनाने के काम में लगे थे लेकिन सरकार उनका सहयोग करने के बजाए उन्हें प्रताड़ित कर रही है।

अनिरुद्ध सिंह

राज्य सरकार प्रदेश में ग्रामीण विकास व पंचायतीराज विभाग के तहत बनने वाले भवनों के लिए भूमि दान करने वाले व्यक्ति के नाम की पट्टिका उस भवन में लगाएगी। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज मशोबरा खंड के नालाग्राम पंचायत घर के लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना भी

जारी कर दी जाएगी। इससे पहले अनिरुद्ध सिंह ने चियोग, देहना, कडरब और नाला गांव में जनसतस्याएं भी सुनी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों के उदघाटन व शिलान्यास भी किए।

मौसम

पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते प्रदेश के उंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात और निचले, मध्यम व मैदानी इलाकों में वर्षा हो रही है। चंबा जिले के मणिमहेश, कुगती व होली में दो सेंटीमीटर जबकि लाहौल स्पिति जिले के केलंग में पांच सेंटीमीटर ताजा हिमपात हुआ है। किन्नौर जिले के छितकुल व नाको और कुल्लू जिले के धुंधी में अटल टनल के आसपास के इलाके में करीब दो इंच ताजा बर्फबारी हुई है। चंबा के उपायुक्त रेपसवाल ने बताया कि ताजा बर्फबारी के चलते पांगी घाटी का सड़क सम्पर्क शेष विश्व से कट गया है।

इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि प्रदेश के 8 जिलों चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू, लाहौल स्पिति, किन्नौर, मण्डी और ऊना में आगामी 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का ओरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रदेश के उच्च पर्वतीय इलाकों में कहीं-कहीं बर्फबारी की संभावना है। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है।

मुख्य सचिव

मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने आज शिमला में सर्दियों के मौसम की तैयारियों के दृष्टिगत आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारियों को किरतपुर-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी हिस्सों में कम से कम दो लेन निरंतर खुला रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पर्यटकों व स्थानीय लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभागों को सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने चाहिए।

अखिलेश कपूर

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अखिलेश कपूर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को एक हजार 6 सौ 33 नए मकान बनाने की मंजूरी दी है। कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सोच को दर्शाता है, जिसमें हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन और सुरक्षित आवास का अधिकार देने का संकल्प निहित है। अखिलेश कपूर ने कहा कि केंद्र द्वारा दी गई यह मंजूरी विशेष परियोजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत की गई है।

मुख्य समाचार एक बार फिर''

- पिछले दो दशकों में प्रदेश के वन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज— वन क्षेत्र बढ़कर हुआ 15 हजार 5 सौ 80 वर्ग किलोमीटर से अधिक।
- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कनाडा के भारतीय प्रवासियों को हिमाचल में निवेश के लिए किया आमंत्रित।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर आपदा प्रभावितों के प्रति अमानवीय व्यवहार अपनाने का लगाया आरोप।
- प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और निचले इलाकों में वर्षा से तापमान में गिरावट— आगामी 24 घंटों में 8 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट।

और

- मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने सभी विभागों को सर्दियों से पहले आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा।

=====